विवरण

क्रम सं.	शोधनशाला का नाम	कार्य आरम्भ करने की तिथि/वर्ष
1.	इंडियन आयल कारपोरेशन, दिग्बोई शोधनशाला	1901
2.	आई ओ सी, गोहाटी शोधनशाला	जनवरी, 1962
3.	आई ओ सी, बरौनी शोधनशाला	जुलाई, 1964
4.	आई ओ सी, हल्दिया शोधनशाला	अगस्त, 1974 (ट्रियल रन) (जनवरी, 1975 से व्यवसायिक उत्पादन)
5.	आई ओ सी, मथुरा शोधनशाला	जनवरी, 1982
6.	आई ओ सी, कोयाली शोधनशाला	अक्टूबर, 1965
7.	एच पी सी, एल बम्बई शोधनशाला	जुलाई, 1954
8.	एच पी सी, एल विशाख शोधनशाला	अप्रैल, 1957
9.	बी पी सी, एल बम्बई शोधनशाला	जनवरी, 1955
10.	कोचीन शोधनशाला	सितम्बर, 1966
11.	मद्रास शोधनशाला	सितम्बर, 1969
12.	बोंगाईगांव शोधनशाला	फरवरी, 1979

प्राकृतिक गैस

1432. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्राकृतिक गैस की मौजूदा स्थिति क्या है और यह कहां-कहां उपलब्ध है और इसके कहां-कहां प्राप्त होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : 1.1.1985 को देश में गैस के शेष प्राप्य भण्डार करीब 479 बिलियन घन मीटर हैं । गुजरात, राजस्थान, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी तटीय और अण्डमान के अपतटीय क्षेत्रों में गैस मिली है । निश्चित रूप से ऐसा पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है कि गैस कहां मिलने वाली है ।

Village electrification in Andhra Pradesh

1433. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the number of villages in each district of Andhra Pradesh which have not yet been electrified;

(b) the number of villages in each district of Andhra Pradesh which are proposed to be electrified during the 7th Five Year Plan, year-wise; and

(c) by when all the villages in Andhra Pradesh are likely to be electrified?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) A Statement indicating the district-wise position of villages remaining to be electrified, in Andhra Pradesh as on 31-3-1985 is enclosed (See below).

(b) and (c) All the villages of Andhra Pradesh are proposed to be electrified during Seventh Five Year Plan. District-wise details of the programme are, however, finalised on annual basis, taking into account the resources position, infrastructural facilities and availability of power etc.